भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3024

जिसका उत्तर 11 मार्च, 2026 को दिया जाना है ।

20 फाल्गुन, 1947 (शक)

इंडिया एआई मिशन का कार्यान्वयन

3024. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2024 में इसके शुभारंभ के बाद से इंडिया एआई मिशन के तहत किए गए कुल बजटीय आवंटन और पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुमोदित राशि का वर्ष-वार और घटक-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) अनुसंधान, स्टार्टअप और शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान करने के लिए हाई-एंड कॉमन कंप्यूटिंग सुविधा की स्थापना और प्रस्तावित ओपन जीपीयू मार्केटप्लेस की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ग) क्या मिशन ने एआई बुनियादी ढांचे, अनुसंधान और नैतिक शासन से संबंधित अपने शुरुआती मील के पत्थर हासिल कर लिए हैं; और
(घ) कंप्यूटिंग संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने और कुछ बड़े निगमों के बीच एआई बुनियादी ढांचे के संकेंद्रण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): भारत की एआई रणनीति प्रौद्योगिकी के उपयोग को लोकतांत्रिक बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका उद्देश्य भारत केंद्रित चुनौतियों का समाधान करना, सभी भारतीयों के लिए आर्थिक और रोजगार के अवसर पैदा करना है।

<u>इंडियाएआई मिशन:</u>

मार्च 2024 में, भारत सरकार ने देश में समग्र एआई इकोसिस्टम के विकास के लिए 10,372 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इंडियाएआई मिशन शुरू किया।

24 महीने से भी कम समय में, भारत एआई मिशन ने देश में एआई इकोसिस्टम के विकास की नींव रखी है:

- सामान्य कंप्यूट सुविधा के लिए 38 हजार से अधिक जीपीयू को शामिल किया गया है, जो भारतीय स्टार्ट-अप और शिक्षाविदों को सस्ती दर पर प्रदान किए जा रहे हैं
- स्वदेशी मूलभूत मॉडल या लार्ज भाषा मॉडल के विकास के लिए बारह टीमों को चुना गया है
- भारत विशिष्ट एआई एप्लीकेशनों को विकसित करने के लिए तीस आवेदनों को मंजूरी दी गई है
- प्रतिभा विकास के लिए आठ हजार से अधिक स्नातक छात्रों, पांच हजार स्नातकोत्तर छात्रों और पांच सौ पीएचडी छात्रों को सहायता प्रदान की जाती है
- 27 इंडिया डेटा और एआई प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं और 543 और की पहचान की गई है
- 5 नवंबर 2025 को जारी इंडिया एआई गवर्नेंस दिशानिर्देश, देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, जिम्मेदार और समावेशी विकास और तैनाती के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करते हैं।

इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट 2026

भारत ने 16-21 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। पहली बार, ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन श्रृंखला ग्लोबल साउथ में हुई।

शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक वैश्विक अभिसरण के रूप में संपन्न हुआ, जिसने भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवाचार, शासन, साझेदारी और समावेशी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया।

'इंडियाएआई मिशन' का कार्यान्वयन 5 वर्षों की अवधि के लिए 10,371.92 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ किया जा रहा है। इसके सात प्रमुख स्तंभों के बीच बजटीय परिव्यय का विस्तृत आवंटन इस प्रकार है:

संघटक	**कुल व्यय** (₹ करोड़)
इंडियाएआई कंप्यूट क्षमता	4563.36
इंडियाएआई फाउंडेशन मॉडल	1971.37
इंडियाएआई डेटासेट प्लेटफॉर्म	199.55
इंडियाएआई एप्लिकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव	689.05
इंडियाएआई फ्यूचरस्किल्स	882.94
इंडियाएआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग	1942.5
सुरक्षित और विश्वसनीय एआई	20.46
इंडियाएआई ओवरहेड्स और आकस्मिकता @1%	102.69
कुल	10,371.92

इंडियाएआई कंप्यूट क्षमता स्तंभ: इंडियाएआई मिशन के तहत इस स्तंभ का उद्देश्य एमएसएमई और स्टार्टअप सहित सभी को सस्ती कीमत पर हाई-एंड कंप्यूट पावर (जीपीयू) प्रदान करना है।

इंडियाएआई कंप्यूट पोर्टल (https://compute.indiaai.gov.in) को सूचीबद्ध एआई क्लाउड सेवाओं की खोज, पहुंच और उपयोग को सक्षम करने के लिए विकसित किया गया है।

राष्ट्रीय एआई कंप्यूट क्षमता का संचालन पैनल में शामिल एआई सेवा प्रदाताओं के माध्यम से किया जाता है जो रियायती दरों पर क्लाउड पर जीपीयू एक्सेस प्रदान करते हैं। चौदह (14) एआई सेवा प्रदाताओं को हाई-एंड एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर तक सस्ती पहुंच प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

जिन डेटा केंद्रों से ये सेवाएं प्रदान की जाती हैं, वे देश के कई क्षेत्रों में स्थित हैं। वर्तमान में, सभी सूचीबद्ध एआई सेवा प्रदाता एमईआईटीवाई-सूचीबद्ध क्लाउड सेवा प्रदाता हैं, जिनके डेटा सेंटर मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, नोएडा और जामनगर जैसे शहरों में स्थित हैं।

इंडियाएआई ने जीपीयू संसाधनों तक पहुंच और सब्सिडी आवंटन को नियंत्रित करने वाली एक अंतिम उपयोगकर्ता नीति को अधिसूचित किया है। योग्य अंतिम उपयोगकर्ताओं में स्टार्टअप, एमएसएमई, शोधकर्ता, शैक्षणिक संस्थान, छात्र और सरकारी संस्थाएं शामिल हैं।

*****